सोशल मीडिया कंपनियां आमने-सामने

ट्विटर ने अदालत की शरण भले न ली हो, लेकिन एक बयान जारी कर कहा है कि वह इन कानूनों के उन प्रावधानों में बदलाव की वकालत करता रहेगा, जो अभिव्यक्ति की आजादी में बाधा डालते हैं।

अमन शाह।।

इस साल 25 फरवरी को घोषित नए आईटी कानूनों को लागू करने के सवाल पर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया कंपनियां आमने-सामने हैं। वॉट्सऐप तो इन कानूनों के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक और निजता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए इनके खिलाफ कोर्ट चला गया है। ट्विटर ने अदालत की शरण भले न ली हो, लेकिन एक बयान जारी कर कहा है कि वह इन कानूनों के उन प्रावधानों में बदलाव की वकालत करता रहेगा, जो अभिव्यक्ति की आजादी में बाधा डालते हैं। अन्य सोशल मीडिया कंपनियों ने कानून का पालन करने की मंशा जरूर जताई है, लेकिन वे भी अलग-अलग तरीकों से यह संकेत दे रही हैं कि इन कानूनों का पालन करने में काफी मुश्किलें हैं। जहां तक सरकार की बात है तो उसने अपना कड़ा रुख कायम रखते हुए वॉट्सऐप की आपत्तियों का तत्काल जवाब दिया। उसका कहना है कि लोगों के निजता के अधिकार का वह भी सम्मान करती है, लेकिन कोई भी अधिकार संपूर्ण नहीं होता। उसका कहना है कि एंड-टु-एंड एनक्रिप्शन भंग होने की जो बात वॉट्सऐप कह रहा है, वह आम यूजर्स के केस में वैसे भी लागू नहीं होती।

यह कानून सिर्फ उन्हीं मामलों में लागू किया जाएगा, जहां देश की सुरक्षा, विदेश से संबंध और सार्वजनिक शांति व्यवस्था जैसे मामले जुड़े होंगे। हालांकि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने, इनके जरिए फेक न्यूज फैलाने की जितनी शिकायतें आ रही हैं, उसके मद्देनजर इस पर विवेक का अंकुश लगाने की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर ध्यान देने की बात यह भी है कि यह कानून सिर्फ सोशल मीडिया कंपनियों पर नहीं बल्कि मीडिया संस्थानों के डिजिटल संस्करणों पर भी लागू किया जाना है, जिनमें कॉमेंट सेक्शन होते हैं। इस पर अलग से भी काफी कुछ कहा जा चुका है कि मीडिया संस्थानों को इसमें शामिल करना न केवल अनावश्यक बल्कि खतरनाक भी है। लेकिन अभी तक सरकार ने इन कानूनों में किसी तरह का बदलाव लाने का संकेत नहीं दिया है। दूसरी बात यह कि कौन सा कंटेंट आपत्तिजनक माना जाएगा, यह तय करने का कोई आधार स्पष्ट नहीं है। जाहिर है, सोशल मीडिया कंपनियों को सभी कॉमेंट्स और संदेश अपने दायरे में रखने होंगे। पता नहीं किस कॉमेंट को आपत्तिजनक मान लिया जाए, किन संदेशों की ओरिजिन पूछ दी जाए। यानी वॉट्सऐप मेसेज भी भेजने वाले और पाने वाले के बीच सीमित चीज नहीं रह जाएंगे।

भले सरकार कह रही हो कि इस कानून का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं मामलों में किया जाएगा, जिनमें और कोई उपाय न रह गया हो, लेकिन कोई उपाय रह गया है या नहीं, यह भी तो सरकार ही तय करेगी। पिछले दिनों सरकार ने सोशल मीडिया के खिलाफ जिस तरह का रुख दिखाया है, उससे संदेह बढ़ा है। बेहतर होगा कि सरकार इस मामले में बलपूर्वक आगे बढ़ने के बजाय बातचीत के जरिए संदेह दूर करते हुए आगे बढ़े।

विश्वास कीजिए!

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। क्या तू भी देखेगा?" और उन्होने विवेकानंद को स्पर्श किया और विवेकानंद उस परमेश्वररूपी शून्य में विलीन होते चले गए।

विश्वास कीजिए! यही एक मात्र मार्ग है गुरु को खोजने का और इसी मार्ग से सनातन संस्कृति के अनगिनत लोगों ने उस परमेश्वर को प्राप्त किया है।

आज के समय में जिस प्रकार सनातनियों को एक डरा हुआ प्राणी बना दिया गया है वैसा सनातन संस्कृति का उद्देश्य नहीं है। आज के समय में पुरोहितों द्वारा कर्मकांड को एक छड़ी की तरह प्रयोग में लाया जा रहा है। जिससे कि हमें डराया जा सके और उनका व्यवसाय चलता रहे। हमने प्रायः पुरोहितों द्वारा सुना है कि "तुम अमुक कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ अमुक घटना घट सकती है" "ऐसा किया तो भगवान तुम पर क्रोधित हो जाएंगे" "हम तुम्हारे लिए अमुक पूजा कर देंगे और मनवांछित फल मिल जाएगा" "अमुक इच्छापूर्ति के लिए ये अमुक पूजा करनी है"।

संपादकीय

उत्तराधिकार का मामला

दलाई लामा के 86 पार करने पर निर्वासित तिब्बतियों के बीच इस बात को लेकर भी बातचीत जारी है कि दलाई लामा के बाद उनकी लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी। इसमें एक पहलू उनके उत्तराधिकार का है, जिस पर अमेरिका ने अपने यहां कानून पारित कर रखा है और चीन के बाहर पूरी दुनिया में इस पर सहमति है कि यह मसला तिब्बतियों को ही तय करने दिया जाना चाहिए। खुद चीन का कहना है कि किसी भी बड़े लामा का अवतार चीन सरकार की मोहर के बिना सत्यापित नहीं होता। लेकिन अंततः यह एक धार्मिक मसला है। कल को चीनी अपनी मोहर वाला 15वां दलाई लामा खड़ा भी कर देंगे तो कोई तिब्बती उसे पूजने नहीं जाएगा। बहरहाल, निर्वासित तिब्बतियों के लिए चिंता इससे आगे की है। तिब्बती बौद्ध धर्म के चार संप्रदायों में सैकड़ों साल से आपसी लड़ाइयां चल रही हैं और वे हाल तक जाहिर होती रही हैं। दलाई लामा अपनी लड़ाई को सांस्कृतिक स्वायत्तता की मांग तक सीमित रखते हैं, जिस पर निर्वासित तिब्बतियों की नई पीढ़ी दबे ढंग से उनके प्रति नाराजगी भी जताती रही है। लेकिन दलाई लामा को गांधी का आध्यात्मिक बेटा यूं ही नहीं कहा जाता। 14वें दलाई लामा के बाद वे अपनी मर्जी का दलाई लामा तो चुन लेंगे, लेकिन उसके मजबूत होने तक तिब्बतियों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा? निर्वासित तिब्बती संसद और खासकर प्रधानमंत्री पेनपा त्सेरिंग को अब इस पहलू पर ज्यादा काम करना चाहिए।

भारत आधिकारिक रूप से तिब्बत को चीनी लोक गणराज्य का अंग मानता है। उसकी भूमिका चीन के एक निर्वासित, असंतुष्ट धार्मिक-राजनीतिक नेता और उनके अनुयायियों को शरण देने तक सीमित है।

युद्ध-शांति के बीच

चंद्रभूषण।।

86 साल के दलाई लामा अभी किसी को राजनीतिक या कूटनीतिक चुनौती देने की स्थिति में नहीं हैं। जब वे इस स्थिति में थे, तब भी उनकी कार्यशैली चुनौती देने वाली नहीं थी। अभी भारतीय प्रधानमंत्री ने उनके जन्मदिन पर उन्हें शुभकामना दी और इस सूचना को ट्वीट भी किया तो इसे बड़ी कूटनीतिक पहल के रूप में लिया गया। कहा गया कि किसी और भारतीय प्रधानमंत्री ने कभी सार्वजनिक रूप से दलाई लामा को शुभकामना नहीं दी थी। लेकिन यह कहते हुए कम लोगों को याद रहता है कि मौजूदा प्रधानमंत्री को भी सत्ता में आए आठवां साल चल रहा है। उन्होंने न केवल स्वयं पहले अपनी ऐसी किसी पहल को सार्वजनिक नहीं किया, बल्कि 2018 में बाकायदा अपने मंत्रियों और अधिकारियों को ताईद की थी कि वे भी ऐसा कोई दिखावा न करें।

भारत आधिकारिक रूप से तिब्बत को चीनी लोक गणराज्य का अंग मानता है। उसकी भूमिका चीन के एक निर्वासित, असंतुष्ट धार्मिक-राजनीतिक नेता और उनके अनुयायियों को शरण देने तक सीमित है। भारत में वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर से अपनी निर्वासित संसद और सरकार चलाते हैं, लेकिन भारत सरकार ऐसी गतिविधियों के सक्रिय समर्थन

में खड़ी नहीं दिखना चाहती। कम से कम पिछले साल के प्रथमार्ध तक यही स्थिति रही। 15 जून 2020 को लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर खून बहा, हालांकि गोलियां नहीं चलीं। यह युद्ध और शांति के बीच की स्थिति है, लिहाजा बहुतेरी राजनयिक प्रतिबद्धताएं हिल-डुल स्थिति में हैं। भारतीय प्रधानमंत्री का दलाई लामा के लिए जन्मदिन शुभकामना ज्ञापन इस बदलाव को ही जाहिर करता है।

कुछ लोगों का आग्रह है कि इस हिल-डुल स्थिति की छाप दलाई लामा और भारत स्थित तिब्बतियों के व्यवहार में भी दिखनी चाहिए और चीन की जोर-जबर्दस्ती के खिलाफ उन्हें कुछ तो बोलना चाहिए। यह वाकई टेढ़ा मामला है। तिब्बत में चीन सरकार तिब्बतियों की फौजी भर्ती करके सीमावर्ती क्षेत्रों में उनकी बहुलता वाली पलटनें लगाने में जुटी है। इसके अलावा तिब्बतियों की दो और प्रतिरक्षा पंक्तियां खड़ी करने की पहल चीन द्वारा ली जा रही है। एक, हल्की सैनिक ट्रेनिंग वाली जन मिलिशिया खड़ी करना और दूसरी दुर्गम सीमा क्षेत्रों में घुमंतू चरवाहों के गांव बसाना, जिनका काम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर छोटे से छोटे बदलाव पर नजर रखना है।

भारत ने चकराता (उत्तराखंड) में तिब्बतियों की जो टूटू रेजिमेंट खड़ी थी, उसने पिछले साल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के रूप में पैंगोंग त्सो के दक्षिणी हिस्से में अपना कमाल दिखा दिया था। जाहिर है, भारत-चीन टकराव की मौजूदा स्थिति में तिब्बती बनाम तिब्बती जैसे किसी दृश्य से चीन पर बना दबाव बढ़ने के बजाय कुछ कम ही होगा। हमारा परिचय निर्वासित तिब्बतियों से है, लेकिन जरूरत तिब्बत में रह रहे तिब्बतियों की मानसिकता समझने की है। असली लड़ाई उन्हीं की है, जो तिब्बत से बाहर चले आए उनकी नहीं। दलाई लामा की राय हमेशा से इस लड़ाई को मध्यमार्ग के जरिये लड़ने की रही है। अपनी इस राय पर अडिग रहने के लिए उन्होंने अपने बड़े भाई ग्यालो थोंडुप तक से दूरी बना ली, जो तिब्बत की आजादी के लिए सारे तिब्बतियों में सबसे ज्यादा सक्रिय रहे और इसमें सीआईए का सक्रिय सहयोग मिलने की बात भी बाकायदा किताब लिखकर स्वीकार की।

सूडोकु नवताल-5407

मध्यम

6	9			7	4		8	
	8	5	6	2			4	9
7						6		3
	3	9	5				1	
1				8				5
	6				2	9	3	
4		7						2
8	2			5	9	1	7	
	1		2	3			5	8

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5406 का हल

8	5	3	9	1	7	2	6	4
9	1	8	2	6	4	3	7	5
7	4	2	5	3	8	1	9	6
3	7	1	6	9	2	4	5	8
8	6	9	1	4	5	7	2	3
5	2	4	8	7	3	9	6	1
2	9	5	4	8	1	6	3	7
4	3	6	7	5	9	8	1	2
1	8	7	3	2	6	5	4	9

अपना ब्लॉग

मुद्दे भी हवा में उड़ गए

मोहन। द्वितीय विश्वयुद्ध से लेकर अब तक दुनिया में न जाने कितने सशस्त्र विद्रोह पूरी तरह कुचल दिए गए और समय के साथ उनके मुद्दे भी हवा में उड़ गए। लेकिन तिब्बत का मुद्दा आज भी दुनिया के लिए मौजूं बना हुआ है तो इसकी अकेली वजह यह है कि उसे दलाई लामा का नेतृत्व हासिल है। हम इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि निर्वासित तिब्बतियों में कितनी तरह के क्षेत्रीय और सांप्रदायिक टकराव मौजूद हैं। पूर्वी तिब्बत का लड़ाकू खाम इलाका खुद को लंबे समय से ल्हासा के आधिपत्य से मुक्त मानता आया है। लेकिन दलाई लामा के प्रभाव में ये सारे टकराव इतने मंद पड़ गए हैं कि बाहरी लोग उनके बारे में नहीं जानते और निर्वासित तिब्बती संसद में हर खेमा तिब्बत की आजादी या स्वायत्तता के साझा मुद्दे पर एकजुट दिखता है। इस लड़ाई को ज्यादा उग्र बनाने पर भीतरी टकराव उभर आने का भी खतरा है।